खण्ड-06 सत्र -05 (भाग-01) / अंक-44

सोमवार

6 मार्च, 2017 / 15 फाल्गुन, 1938 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

छठी विधान सभा

पांचवां सत्र

अधिकृत विवरण

(सत्र-05 (भाग-01) में अंक 44 से अंक 48 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा

सचिव

PRASANNA KUMAR SURYADEVARA

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editing)

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा प्रिन्टो ग्राफ, 2266/41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-5 भाग (1) सोमवार, 6 मार्च, 2017/15 फाल्गुन, 1938 (शक) अंक-44

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे समवेत हुआ।

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची:

1. श्री पंकज पुष्कर
2. श्री पवन कुमार शर्मा
3. श्री अजेश यादव
4. श्री महेंद्र गोयल
5. श्री वेद प्रकाश
6. श्री सुखवीर सिंह दलाल
7. श्री ऋतुराज गोविंद
8. श्री संदीप कुमार
9. श्री रघुविन्द्र शौकीन
10. श्रीमती बंदना कुमारी
11. श्री राजेश गुप्ता
12. श्री सोमदत्त
13. सुश्री अलका लाम्बा
14. श्री आसिम अहमद खान
15. श्री विशेष रवि
16. श्री हजारी लाल चौहान
17. श्री गिरीश सोनी
18. श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर)
19. श्री राजेश ऋषि
20. श्री महेंद्र यादव

21. कर्नल देवेंद्र सहरावत
22. सुश्री भावना गौड़
23. श्री सुरेंद्र सिंह
24. श्री विजेंद्र गर्ग
25. श्री प्रवीण कुमार
26. श्री मदन लाल
27. श्री सोमनाथ भारती
28. श्रीमती प्रमिला टोकस
29. श्री नरेश यादव
30. श्री करतार सिंह तंवर
31. श्री प्रकाश
32. श्री अजय दत्त
33. श्री दिनेश मोहनिया
34. श्री सौरभ भारद्वाज
35. सरदार अवतार सिंह कालकाजी
36. श्री सही राम
37. श्री नारायण दत्त शर्मा
38. श्री राजू धिंगान
39. श्री मनोज कुमार
40. श्री नितिन त्यागी
41. श्री एस. के. बग्गा
42. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
43. श्री राजेंद्र पाल गौतम
44. श्रीमती सरिता सिंह
45. मो. इशराक
46. श्री श्रीदत्त शर्मा
47. चौ. फतेह सिंह
48. श्री जगदीश प्रधान

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-5 भाग (1) सोमवार, 6 मार्च, 2017/15 फाल्गुन, 1938 (शक) अंक-44

फाइनल/18415

सदन अपराह्न 12.10 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय **(श्री राम निवास गोयल)** *पीठासीन हुए।*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, छठी विधानसभा के पांचवे सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आपको मालूम है कि यह बजट सत्र है। इसमें उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और बजट पर चर्चा करने के दौरान आपको अपने विचार प्रकट करने का भरपूर मौका मिलेगा।

मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे शालीनता से और कम से कम समय में अपनी बात कहें और सदन का समय व्यर्थ न होने दें। सदन के समय का सदुपयोग करना हमारी प्राथमिकता है। अत: आप सबसे मेरा निवेदन है कि सदन की कार्यवाही में नियमित रूप से तथा शालीनतापूर्वक भाग लें और कार्यवाही को सुचारू से चलाने में मुझे सहयोग दें।

अब सचिव, विधानसभा माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति सदन पटल पर रखेंगे।

सचिव, (विधानसभा) : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से माननीय उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण की हिन्दी तथा अंग्रेजी प्रति सदन के पटल पर रखता हूं।

(उपराज्यपाल महोदय का अभिभाषण)

आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं माननीय सदस्यगण,

1. मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की छठी विधानसभा के पांचवें सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं।

2. मेरी सरकार अपने इस दायित्व के प्रति वचनबद्ध है कि प्रत्येक नागरिक को जीवन यापन की सभी बुनियादी सुविधाएं मिलें और सरकार का कर्त्तव्य है कि वह इन आवश्यकताओं को पूरा करे। इसी उद्देश्य को सामने रखते हुए सरकार ने 20 कि.ली. प्रतिमाह जल उपभोग को नि:शुल्क प्रदान करने के निर्णय को जारी रखा है। इसी प्रकार घरेलू उपभोक्ताओं को 400 यूनिट प्रतिमाह तक कम दर पर बिजली प्रदान करने का निर्णय भी जारी रखा गया है।

3. समावेशी विकास के लिए मेरी सरकार ने शिक्षा को महत्वपूर्ण क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया है। शिक्षा के स्तर में सुधार की ओर सरकार का ध्यान केन्द्रित होने के फलस्वरूप दिल्ली के विद्यार्थियों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। शैक्षणिक सत्र 2015-16 में 12वीं कक्षा के सरकारी स्कूलों का उत्तीर्ण प्रतिशत 89.25 तथा दसवीं कक्षा का 95.81 प्रतिशत रहा। इसी सत्र में राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालयों का प्रीक्षण परिणाम 99.62 प्रतिशत रहा।

4. शैक्षणिक अवसंरचना में सुधार के लिए 20 नए स्कूल भवनों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। इनमें से 14 स्कूल भवनों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। विद्यार्थियों और कमरों के अनुपात में सुधार लाने के लिये

विभिन्न विद्यालयों में लगभग 8000 अतिरिक्त कमरों का निर्माण किया जा रहा है (लोक निर्माण विभाग द्वारा 146 स्कूलों में 7289 अतिरिक्त कमरे तथा डी.टी.टी.डी.सी. द्वारा 54 स्कूलों में लगभग 800 अतिरिक्त कमरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है)।

5. चालू शिक्षा सत्र 2016–17 के दौरान 5 नए स्कूल खोले गए है 5 को अपग्रेड किया गया है और 7 अन्य स्कूलों को बाइफर्केट करते हुए विभिन्न स्तरों पर विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता को बढ़ाया गया है। विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य के लिए 4 और स्कूलों में विज्ञान विषयों को शुरू किया गया है।

6. शिक्षा निदेशालय के मूलभूत मूल्यांकन के आधार पर सामने आया कि कक्षा 6 में पढ़ने वाले 74 प्रतिशत बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तकें पढ़ नहीं सकते या आधारभूत गणित को समझ नहीं सकते। जानकारी की इस कमी को समाप्त करने के लिए सरकार ने ''चुनौती 2018'' शुरू किया है।

7. 5 सितम्बर, 2016 से 14 नवम्बर, 2016 के दौरान एक विशेष ''पढ़ाई अभियान'' चलाया गया, जिसमें स्कूलों में रीडिंग होम तथा समुदाय स्तर पर रीडिंग मेलों को शामिल किया गया। इससे पढ़ने की जानकारी न रखने वाले एक लाख बच्चों को पढ़ने की योग्यता प्रदान की गई।

8. विद्यार्थियों के अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी और शिक्षा की गुणवत्ता में और अधिक सुधार के लिये पहली बार दिल्ली सरकार के स्कूलों में जुलाई, 2016 तथा अक्तूबर, 2016 में विशाल अभिभावक-शिक्षक बैठकों का आयोजन किया गया।

9. सरकार ने स्पोर्ट्स अकादमियों के माध्यम से सरकारी स्कूलों में खेलकूद

संबंधी कोचिंग और प्रशिक्षण शुरू किया है। प्रथम चरण में 55 अकादमियों को अनुमति प्रदान की गई है कि वे लगभग 100 स्कूलों के खेल के मैदानों का उपयोग कर सके। जन सामान्य के लिए भी सत्तर (77) सरकारी स्कूलों के खेल के मैदानों को खोल दिया गया है। 54 मॉडल सरकारी स्कूलों में पाठ्यक्रम से हटकर संगीत, नृत्य, नाट्य कला आदि में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए है।

10. सरकार ने 500 स्कूलों में ग्रीष्मकालीन कैम्पों का भी आयोजन किया। 1024 हैडस ऑफ स्कूल को नेतृत्व करने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

11. सरकारी एजेंसियों द्वारा आवंटित भूमि पर बने प्राइवेट स्कलों की मनमाने ढंग से फीस बढ़ोतरी की रोकथाम करने और विनियमित करने में सरकार सफल रही है।

12. 26 सितम्बर, 2016 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा जर्मन फेडरल फ्री स्टेट ऑफ थुरिंजिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ताकि विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षा केन्द्रों तथा अनुसंधान संस्थानों के बीच में विभिन्न क्षेत्रों जैसा कि शिक्षकों, शैक्षणिक प्रकाशनों, सूचनाओं और सहयोगी अनुसंधान के विकास क्षेत्र में आदान-प्रदान किया जा सके।

13. विद्यार्थियों के शिक्षण ऋण की सुविधा के लिये 20.06.2016 से वेब-पोर्टल के माध्यम से ऑन लाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई है।

14. उच्च शिक्षा के लिए अवसंरचना को ठोस बनाने के उद्देश्य से अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली के लिए रोहिणी तथा धीरपुर में नए कैम्पस का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना का निर्माण कार्य नवम्बर, 2020 तक पूरा हो जाएगा।

15. अम्बेडकर विश्वविद्यालय के कर्मपुरा कैम्पस में 2016-17 का सत्र शुरू हो चुका है और स्नातक पूर्व पाठ्यक्रम के लिए 209 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है। दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज ने 20.07.2016 से द्वारका के नए भवन में अपना कार्य शुरू कर दिया है।

16. महर्षि बाल्मिकी शिक्षा महाविद्यालय के नए कैम्पस का निर्माण रोहिणी में शुरू किया जा चुका है। महर्षि बाल्मिकी शिक्षा महाविद्यालय के नए कॉलेज कैम्पस के लिए रोहिणी सैक्टर-16 के समीप डीडीए ने भूमि का आवंटन कर दिया है।

17. महिलाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 7 नए कॉलेजों में नॉन-कॉलेजिएट वुमैन एजुकेशन सैन्टर (एनसीडब्ल्यूईसी) शुरू किए जा चुके है। इन केन्द्रों में शिक्षा सत्र 2016-17 से प्रत्येक कॉलेज में 470 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता से शिक्षण कार्य शुरू हो चुका है।

18. मेरी सरकार ने कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया है, विभिन्न तकनीकी कौशल की शिक्षा प्रदान करने के लिए अनेक आईटीआई में विभिन्न ट्रेड शुरू किए गए हैं। सरकार के नये आईटीआई बनाने की परियोजना का कार्य प्रगति पर है। चरण-II के आईआईआईटी-दिल्ली का निर्माण कार्य अगस्त, 2017 तक पूरा होने की संभावना है जिसमें अतिरिक्त, 1400 विद्यार्थियों को स्थान मिलेगा। जौनापुर में एक विश्वस्तरीय कौशल केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इस समय यह विवेक विहार में अस्थायी स्थल पर चलाया जा रहा है और आतिथ्य कार्यो, खुदरा सेवाओं, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, लेखा एवं बैंकिंग वित्त का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 5 नए पॉलिटेक्निक भी खोले जाएंगे।

19. दिल्ली को स्टार्ट-अप हब बनाने हेतु वर्ष 2015-16 में एक इन्क्यूबेशन पॉलिसी तैयार की गई थी। इसके अन्तर्गत शुरूआत में विश्वविद्यालय संस्थानों में छः इन्क्यूबेशन केन्द्र खोले गए, और पांच नए संस्थान जोड़े गये हैं।

20. अपने नागरिकों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के प्रति मेरी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। इस समय 36 मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल कार्यरत है, जिनमें 6 सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल भी शामिल है और इनमें 11,000 से अधिक बिस्तर के साथ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीजों के लिये 69 निजी अस्पताल में निःशुल्क चिकित्सा हेतु 731 बिस्तर उपलब्ध है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूर-दराज न जाना पड़े, इसके लिए सरकार ने विकेन्द्रित स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अनेक स्थानों पर मौहल्ला क्लीनिक शुरू किए है। इस प्रयास की सराहना अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर श्री कोफी अन्नन, पूर्व महासचिव संयुक्त राष्ट्र महासंघ और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा की गई है। वर्तमान में 103 आम आदमी मौहल्ला क्लीनिक चलाए जा रहे है। 1000 मौहल्ला क्लीनिकों को अगले छः माह में बनाया जायेगा और अगले एक साल में 122 पॉली क्लीनिक तैयार किये जायेंगे। चिकित्सा क्षेत्र में शिक्षा अनुसंधान और नई प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण के माध्यम से सरकार जन स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने का प्रयास कर रही है। इस दिशा में रोहिणी में एमबीबीएस कोर्स के लिए 100 सीटों के साथ डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर कॉलेज शुरू किया गया है।

21. मेरी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार के लिए भरसक प्रयास कर रही है। विभिन्न प्रयोजनाओं के शीघ्र पूर्ण होने पर अस्पतालों में 10,000

अतिरिक्त बिस्तर उपलब्ध होंगे। द्वारका, बुराडी, अम्बेडकर नगर तथा दीन दयाल अस्पताल में बिस्तरों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा विद्यमान 22 सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या 2000 तक बढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। 3 नए अस्पताल नांगलोई, सिरसपुर तथा मादीपुर में बनाए जाएंगे, जिसमें 1800 रोगी भर्ती हो सकेंगे।

22. गरीब रोगियों को निःशुल्क डायलेसिस करवाने के लिये निजी सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) परियोजना के अन्तर्गत लोक नायक अस्पताल, राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में 40 मशीने लगाई गई हैं। डॉ हेडग्रेवार आरोग्य संस्थान में इस वित्त वर्ष में 20 मशीने लगाई गई है। सरकार ने दिल्ली के निवासियों के लिए एमआरआई, सीटी, पीईटी इत्यादि जैसे रेडियोलॉजी जांच को भी निःशुल्क कर दिया है।

23. एम्बुलेंस के बेड़े में 110 नई एम्बुलेंस बढ़ाई गई हैं तथा एम्बुलेंस की सेवाओं को विनियमित करने के लिए मॉडल कंट्रोल रूप स्थापित किया गया है। सरकार ने ''होम-टू-हॉस्पिटल केयर'' नामक एम्बुलेंस सेवा स्कीम 3 जुलाई, 2016 से शुरू की है। आपातकालीन चिकित्सा के लिये कैट्स द्वारा निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा प्रदान की जा रही है।

24. सरकार गरीब जनता और अत्यधिक गरीब तबके की सहायता के लिये विशेष प्रयास कर रही है। इसके लिए समाज कल्याण विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग व्यक्तियों, संकट ग्रस्त महिलाओं आदि के लिये विभिन्न आर्थिक सहायता स्कीमें चला रही है। मेरी सरकार ने वृद्धावस्था, दिव्यांगता एवं विधवा पेंशन को प्रतिमाह 1000/- रुपये बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि वृद्धों,

दिव्यांगो और महिलाओं की पात्रता की आय सीमा बढ़ाकर एक लाख रुपये प्रतिवर्ष कर दी जाए।

25. श्रमिकों के लिए कल्याणकारी कार्यों के प्रति दिल्ली सरकार वचनबद्ध है। दिल्ली सरकार ने 1.4.2016 से अकुशल कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 9568/- रुपये प्रतिमाह कर दिया था। यह बढ़ोतरी अर्धकुशल कामगारों के लिए 10,582/- रुपये तथा कुशल कामगारों के लिए न्यूनतम 11,622/- रुपये प्रतिमाह की गई थी। हाल ही में मेरी सरकार ने अकुशल, अर्धकुशल तथा कुशल श्रेणी के कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन क्रमशः 13,350/- 14,698/- एवं 16,182/- रुपये प्रतिमहा बढ़ा दिया है।

26. बेघरों को राहत प्रदान करने के लिए 197 रैन बसेरे बनाए गए हैं, जिनकी क्षमता 16174 है और इसमें सभी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की गई है। इनमें से महिलाओं, बच्चों, दिव्यांग परिवार के लोगों, नशे के आदि व्यक्तियों के लिए 52 रैन बसेरे निश्चित किए गए है। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में बेघरों को उचित स्थान पर पहुंचाने के लिए 23 राहत टीमें और वाहन लगाए गए। बेघर लोगों की शिकायत/सूचना प्राप्त करने के लिए चौबीसों घंटे नियंत्रण कक्ष स्थापित किये गए।

27. बेघर युवाओं को रोजगार के लिए कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से 10 कौशल विकास केन्द्र शुरू किए गए है। इन केन्द्रों में युवाओं को सिलाई, ब्यूटी पार्लर, बिजली मरम्मत आदि का प्रशिक्षण कुशल अध्यापकों द्वारा दिया जाता है।

28. सरकार ने घटना स्थल पर मौजूद ऐसे श्रेष्ठ कर्त्तव्यपराण व्यक्तियों को

प्रशस्ति-पत्र तथा पुरस्कार देने का निर्णय लिया है जो सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाते हैं।

29. सरकार के जन कल्याण की गतिविधियां सुदृढ़ आर्थिक स्थिति पर आधारित है। दिल्ली का सकल घरेलू उत्पाद 2014-15 में 4,94,460 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 5,58,745 करोड़ रुपये होने से 13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। स्थित मूल्यों पर वास्तविक रूप में दिल्ली की अर्थव्यवस्था 2015-16 में 8.34 प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी हुई जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह बढ़ोतरी 7.6 प्रतिशत रही। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में दिल्ली का योगदान लगभग 4.12 प्रतिशत है जबकि दिल्ली की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 1.43 प्रतिशत है।

30. पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली की प्रतिव्यक्ति आय 2015-16 में 2,80,142/- रुपये रही जो कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतिव्यक्ति आय 93,293/- रुपये से तीन गुणा अधिक है। दिल्ली की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का प्रमुख स्थान है और सकल राज्य घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 82.3 प्रतिशत है और तत्पश्चात् औद्योगिक क्षेत्र का 15.5 प्रतिशत, कृषि क्षेत्र का 2.2 प्रतिशत है।

31. मजबूत अवसंरचना व्यवस्था स्थायी प्रगति के लिए अनिवार्य है। पिछले अनेक वर्षों में दिल्ली ने एक मजबूत अवसंरचना का निर्माण कर लिया है तथापि जनसंख्या की बढ़ोतरी के अनुसार पानी की मांग बढ़ी है। कुशल प्रबंधन के माध्यम से पेयजल की लगभग 900 एमजीडी का सर्वोच्च उत्पादन हुआ है तथा पानी की कमी वाले क्षेत्रों में जलापूर्ति बढ़ाने के लिए ट्यूवैल तथा वाटर एटीएम लगाए गए हैं। अब स्टेन्लेसस्टील के नए वाटर टैंकरों द्वारा जलापूर्ति की जा रही है जिनका ऑन लाईन मजबूत

निगरानी प्रणाली से नियंत्रण किया जा रहा है। इस प्रणाली से जनता स्वयं अपने क्षेत्र में पहुंचने वाले टैंकर तथा उसके पानी की गुणवत्ता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

32. सरकार ने जल तथा सीवर विकास प्रभारों को कम किया है और 30 नवम्बर, 2015 तक के सभी प्रकार के बकायों की वसूली से छूट प्रदान की है, इससे बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचा है।

33. अपशिष्ट जल के निपटान की दृष्टि से सीवेज शोधन क्षमता को बढ़ाकर 604 एमजीडी कर दिया गया है, जिसके लिए 6 सीवेज शोधन संयंत्र शुरू किए गए है। जल शोधन की क्षमता को 370 एमजीडी से बढ़ाकर 455 एमजीडी किया गया है।

34. यमुना नदी में गिरने वाले गन्दे पानी की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सभी प्रस्तावित नए शोधन संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें शोधन गुणवत्ता के मानकों की उच्चता बनाए रखने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया है। यमुना की सफाई कार्य को देखते हुए इन्टरसैप्टर सीवर नामक नई परियोजना 85 प्रतिशत तक पूरी हो चुकी है और लगभग 50 एमजीडी गन्दे पानी के बहाव को यमुना में पहुंचने से पहले ही सफाई करके जलशोधन संयंत्रों में शोधित किया जाता है। सितम्बर, 2016 से कॉरोनेशन पीलर पर 70 एमजीडी जल शोधन संयंत्र का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है जिसका 30 माह में पूर्ण होना प्रस्तावित है।

35. जनसंख्या के लगातार बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप नगर में नए आवासों की आवश्यकता है। नई पुनर्वास नीति के अन्तर्गत झुग्गी झोपड़ी निवासियों की जीवन परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए उन्हें जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना

के अन्तर्गत बनाए गए मकानों में बसाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत झुग्गी झोपड़ी बस्ती के निवासियों और अनुसूचित जाति परिवारों के लिए 55,424 बहुमंजिला मकानों का निर्माण किया है। मलिना बस्तियों के पुनर्वास की संशोधित नीति के पश्चात् 4323 परिवारों को अस्थायी आवंटन पत्र दिए गए हैं, जिनमें 1768 अनुसूचित जाति परिवार भी शामिल है।

36. नई भवन उप-विधि को अंगीकार करते हुए तीन नगर निगमों में इसे अधिसूचित करने से सेस्मिक जोन-V की भवन संहिता, 2005 की व्यवस्थाओं का पालन किया जाना अब आवश्यक हो गया है।

37. नगर को साफ-सुथरा बनाए रखने के लिए दिल्ली की तीनों नगर निगम प्रतिदिन 10,000 मैट्रिक टन कूड़ा साफ करती हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् को 12 अगस्त, 2016 से खुले में शौच मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। खुले में शौच की आदत को समाप्त करने की दृष्टि से झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में पे एंड यूज जनसुविधा परिसर बनाए गए हैं, जिनमें शौच और स्नान के लिये व्यवस्था है, इनका प्रबंधन डियूसिब (DUSIB) करता है। स्वच्छ दिल्ली मोबाईल ऐप 16.11.2016 से पुनः शुरू किया गया है जिसमें कूड़ा-करकट/मलबा तथा वायु प्रदूषण संबंधी शिकायतें अपलोड की जा सकती है।

38. मेरी सरकार ने अनाधिकृत कॉलोनियों में आवास परिस्थितियों में सुधार के लिए भी अनेक आवश्यक कदम उठाए हैं। अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास कार्यों में तेजी लाई गई है। चालू वित्त वर्ष में इन कॉलोनियों में विकास कार्यों हेतु 1456 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया था। दिल्ली जल बोर्ड ने अब तक 1175 अनाधिकृत कॉलोनियों में जल कनेक्शन लगा दिया गए हैं।

39. नगर में बिजली की मांग में बढ़ोतरी हो रही है। 1/7/2016 को सर्वाधिक 6261 मेगावाट की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। बिजली की बचत के लिए सभी उपभोक्ताओं को 93/- रुपये की दर से चार एलईडी बल्ब उपलब्ध कराए गए हैं। अभी तक 65 लाख एलईडी बल्ब उपभोक्ताओं को प्रदान किए जा चुके हैं।

40. बिजली वितरण की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए तुगलकाबाद, द्वारका तथा महारानी बाग में 400 के.वी. सब-स्टेशन ट्रांसमिशन लाईन के साथ पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड द्वारा स्थापित किये जा रहे हैं। तीनों स्थानों के लिए भूमि का हस्तांतरण पूरा हो चुका है।

41. दिल्ली सौर ऊर्जा नीति, 2016 को अधिसूचित किया गया है। अभी तक 32 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्रों को शुरू किया जा चुका है। इसमें वर्ष 2025 तक 2000 मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके अंतर्गत सभी सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। 84 मेगावाट के लिए निविदाएं भी आमंत्रित की गई हैं। घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा उत्पादन के आधार पर 2/- रुपये प्रति युनिट का प्रोत्साहन भी दिया गया है।

42. दिल्ली मेट्रो का वर्तमान नेटवर्क 189 कि.मी. है। तीसरे चरण का कार्य जून, 2017 तक पूरा होने की संभावना है। इसके पूरा होने पर कुल नेटवर्क लगभग 330 कि.मी. हो जाएगा। हाल ही में मेरी सरकार ने मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार कार्य के लिए चौथे चरण में कुल 116 कि.मी. के 8 कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया है। चौथे चरण का यह कार्य भी 2021 के अंत तक पूरा हो सकेगा।

43. महिला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली परिवहन निगम की बसों की शामल की शिफ्टों में होम गार्ड तथा मार्शल तैनात किए

गए हैं। सुबह और शाम के व्यस्त समय के लिए दिल्ली परिवहन निगम की लेडीज स्पेशल बसे चलाई जा रही हैं।

44. दिल्ली के नागरिकों की पर्यावरण संबंधी चिन्ताओं को देखते हुए और पर्यावरण संबंधी निगरानी, संरक्षण तथा जागरूकता फैलाने के कार्य में मेरी सरकार लगातार प्रयासरत है। सरकार ने पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण के प्रति अपनी सजगता का परिचय देते हुए दिल्ली वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए अनेक कदम उठाए हैं। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी 6 निगरानी स्टेशनों के माध्यम से वायु की गुणवत्ता पर निगरानी करती है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी ने धूल नियंत्रण मानकों का उल्लंघन करने वाली निर्माण परियोजनाओं पर जुर्माना लगाया है। प्रदूषण की स्थितियों में कार्यवाही के लिए ग्रेडिड इमरजेंसी रिस्पान्स प्लान शुरू किया जा रहा है।

45. इस अवसर पर मैं, बताना चाहता हूं कि मेरी सरकार नागरिक सापेक्ष प्रशासन प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है और मेरा विश्वास है कि आप सभी दिल्ली के चहुँमुखी विकास में मेरी सरकार के प्रयासों में अपना पूर्ण सहयोग तथा योगदान देंगे।

46. माननीय अध्यक्ष महोदय तथा सम्माननीय सदन के सदस्यगण मैंने आपके समक्ष अपनी सरकार के कुछ कार्यों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया है। उप-मुख्यमंत्री/वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में इस पर विस्तृत प्रकाश डालेंगे।

47. इस सत्र के दौरान सभी विषयों पर सार्थक विचार-विमर्श की कामना करता हूं, और आप सबको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।

जय हिन्द

ADDRESS

OF

SH. ANIL BAIJAL

LT. GOVERNOR, DELHI

TO

THE FIFTH SESSION

OF

SIXTH LEGISLATIVE ASSEMBLY

NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

6th March, 2017

Respected Speaker and Hon'ble Members,

1. I warmly welcome you all to the Fifth Session of the Sixth Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi and also convey my best wishes for the New Year.

2. My Government is committed to ensure that every citizen has right to basic needs of life and it's the duty of the Government to fulfil those requirements. Accordingly, Government continues to provide free water upto a monthly consumption of 20 Kilolitre. Similarly, electricity tariff at reduced rates for domestic consumers up to 400 units per month continues.

3. For inclusive development, my Government had identified education as one of the key sectors. As a result of the Government's focused attention for improving the quality of education, students of Delhi have done exceedingly well. At 12th Level, Government Schools recorded a pass percentage of 89.25% while 95.81% pass percentage was achieved at 10th level during academic session 2015-16. Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalayas achieved 99.62% result during the year 2015-16.

4. To improve the educational infrastructure, construction of 20 new school buildings has been taken up. Out of those, construction of 14 school buildings has been completed. Around 8000 additional class rooms (7289 additional class rooms in 146 schools by PWD and approx 800 class rooms in 54 schools by DTTDC) are being constructed in various existing schools for improving the student classroom ratio.

5. During the current Academic Session 2016-17, 05 new schools have been opened, 05 upgraded and 07 bifurcated thereby paving the way for increasing the intake of students at different levels. Science Stream was introduced in 04 more schools to promote Science Education.

6. A Baseline Assessment conducted by the Directorate of Education showed that 74% children in Class VI could not read their textbooks or do basic mathematics. "Chunauti 2018" is being run to bridge the learning deficit in students.

7. "Reading Campaign" was undertaken from 5th September 2016 to 14th November 2016 – with 'Reading Home' in schools and 'Reading Melas' in communities. One lakh children were converted from non-readers to readers.

8. To actively involve the parents of the students and for further improving the quality of education, two Mega Parent Teacher Meetings were organized by the Delhi Government schools, in July 2016 and October 2016 for the first time.

9. Government has started sports coaching & training through private sports academies in Government schools. In the first phase, 55 academies have been permitted to use 100 school playgrounds. Seventy Seven (77) Government School Playgrounds have been opened for the public. Extra Curricular activities relating to music, dance, drama etc have been started in 54 model Government schools.

10. Government has also organized summer camps in 500 Schools. Leadership coaching to 1024 Heads of Schools has been imparted.

11. Government has been able to regulate and prevent arbitrary fee hike in the private schools where land has been allotted by Government agencies.

12. In the field of Higher Education, MoU has been signed between Government of NCT of Delhi and The German Federal Free State of Thuringia on 26th September, 2016 to promote and encourage interaction amongst the Universities, Centres of Higher Education and Research Institutions in various fields; namely exchange of faculty members, exchange of academic publications and information and development of collaborative research.

13. Online web-portal for students to apply online for availing the education loan facility has been launched on 20/06/2016.

14. To upgrade infrastructure for higher education, construction of new campuses has been initiated for Ambedkar University Delhi at Rohini and Dheerpur. It is planned to complete the project by November 2020.

15. The Karampura Campus of Ambedkar University has already started from Session 2016-17 with intake of 209 students for undergraduate courses. Deen Dayal Upadhyaya College has started functioning from a new building at Dwarka w.e.f. 20/07/2016.

16. Construction of the new campus of Maharishi Valmiki College of Education at Rohini has been initiated. DDA has allotted land for construction of new college campus of Maharishi Valmiki College of Education at Sector- 16, Rohini.

17. To give further fillip to women's education, Non-Collegiate Women's Education Centers (NCWEC) have been started in seven

Colleges. These centers have started functioning w.e.f. 2016-17 academic session with an intake capacity of 470 persons in each College.

18. My Government has laid down special emphasis on skill development, large numbers of ITIs are functioning which are imparting skill education in various trades. The Government intends to start new ITIs for which projects are in progress. Phase–II construction of IIIT Delhi is likely to be completed by August 2017 which will accommodate additional 1400 students. World Class Skill Centre is proposed to be set up at Jaunapur. At present it is operating from a temporary site at Vivek Vihar and imparting education in Hospitality Operation, Retail Services, Information & Technology, Accounts and Banking Finance. Further, five new polytechnics will also be set up.

19. To make Delhi a Start up Hub, an incubation policy was framed in the year 2015-16. Initially Six incubation centres in University Institutions were set up. Another five new institutions have been added.

20. My Government is focused on providing affordable Health Services to its citizens. At present, 36 multi specialty hospitals including 6 super specialty hospitals with more than 11,000 beds are functioning. For EWS patients, 69 private hospitals provide 731 free beds. Further, to bring the Health Care near to the masses, Mohalla Clinics as decentralized health reach out venues were introduced, which have received international acclamation from personalities like Mr. Kofi Annan, former Secretary-General of United Nations, etc. At present 103 Aam Admi Mohalla Clinics are functioning.

1000 Mohalla Clinics will be completed in next six months and 122 Polyclinics will be completed in next one year. The Government also intends to improve public health services through medical education, research and training in cutting edge technologies. In this direction, Dr. Baba Saheb Ambedkar Medical College in Rohini with 100 seats for MBBS course has been started.

21. For expansion of health care, my Government is striving hard to further enhance the number of hospitals and beds. Various projects are currently under execution which would provide additional 10,000 beds. Bed capacity will be enhanced at Dwarka, Burari, Ambedkar Nagar and Deep Chand Hospitals. Further, 22 existing Government Hospitals are being remodelled to add another 2,000 beds. It is also proposed to setup 03 new hospitals which will have total capacity of 1800 beds, located at Nangloi, Siraspur and Madipur.

22. For providing free dialysis to poor patients, under the Private Public Partnership (PPP) project, 40 machines are functional at Lok Nayak Hospital and Rajiv Gandhi Super Specialty Hospital. In this financial year dialysis centre has been started at Dr. Hedgewar Arogya Sansthan with 20 machines. Government has also made radiology tests like MRI, CT, PET etc. free for Delhi Residents.

23. The existing fleet of Ambulances has been augmented by inducting 110 new ambulances. A model control room to regulate the Ambulance services has been setup. “Home to Hospital Care” Ambulance Services Scheme has been launched by the Government on 3rd July 2016 and CATS ambulances are providing free ambulance service for medical emergencies.

24. The Government has made special efforts to help the vulnerable population and the poorest of the poor. The Social Welfare Department and Department of Women and Child Development are implementing various schemes of financial assistance for old age pension, disabled person, women in distress etc. My Government has decided to enhance the old age, disability and widow pension by Rs.1,000/- per beneficiary per month. It was also decided to enhance the income limit for eligibility for old age, disability and widow pension to Rs.1 lakh per annum.

25. Government of NCT of Delhi is committed to the welfare of the labourers. With effect from 01.04.2016 Government of NCT of Delhi had increased minimum wage s for unskilled workers to Rs.9568/- per month; for semi skilled workers Rs.10,582/- per month and for skilled workers, the minimum rate is Rs.11,622/- per month. Only recently my Government has increased wages of unskilled workers to Rs.13,350/- per month, for semi skilled workers to Rs.14,698/- per month and for workers who are in the skilled category to Rs.16,182/- per month.

26. To provide relief to the homeless, 197 Night Shelters having a capacity of about 16174 inmates are being operated and managed with all the basic amenities. Out of these, 52 Night Shelters are exclusively for women, children, families of differently abled persons, drug addicts etc. Besides, 23 Rescue Teams are deployed with vehicles and manpower during winter, to rescue homeless. Round the clock Control Room has been established to receive complaints/information about homeless people.

27. To equip homeless youth with skills for employment, 10 skill development centres have been started. At the centres, the homeless

will be trained by qualified teachers in skills like sewing, beauty parlour, electrical work etc.

28. Government has decided to offer reward and appreciation certificate to those good Samaritans or bystanders who rush road accident victims to hospital.

29. The welfare activities of the Government are pivoted on a strong economy. The Gross State Domestic Product (GSDP) of Delhi at current prices increased from Rs.494460 crore in 2014-15 to Rs.558745 crore in 2015-16 registering a growth of 13%. In real terms at constant prices, Delhi's economy grew at the rate of 8.34% during 2015-16 as compared to 7.6% growth at the national level. Delhi's contribution to the National level GDP is about 4.12%, while the share of Delhi in the total population of the country is 1.43%.

30. The per capita income in Delhi at current prices in 2015-16 is Rs. 2,80, 142 as per advance estimates of Gross State Domestic Product (GSDP), which is 3 times higher than the per capita income of Rs.93,293 at national level. Delhi's economy has a predominance of Service Sector with a share of 82.3% of GSDP followed by Industry with a share of 15.5% and Agriculture having a share of 2.2% of GSDP.

31. To sustain development, a strong infrastructure is a must. Over the years Delhi has developed a robust infrastructure. However, with increasing population there has been increase in demand for water. Through efficient management, peak production of about 900 MGD of potable water has been achieved. To augment water supply in water deficit areas, tube wells and water ATMs have been installed.

New Stainless steel water tankers have been added and web based online tanker monitoring system has been strengthened. Through this internet based system, people can track the tanker coming to their locality and quantity of water it is carrying.

32. Government has reduced Water and Sewer Development Charges and all the arrears till 30th November 2015 have been waived, which has benefited a large number of consumers.

33. In the direction of waste water disposal, Sewage treatment capacity has been augmented to 604 MGD by commissioning 6 sewage Treatment Plants. Utilization of sewage treatment has increased from 370 MGD to 455 MGD.

34. For improvement in quality of waste water discharged into the Yamuna River, all the proposed new STPs are being set up with latest technology to achieve higher treatment quality standards. For cleaning of the river Yamuna, the innovative project of Interceptor Sewer has been completed to the extent of 85% and about 50 MGD waste water flows have been trapped from the drains and are now being treated at the Sewage Treatment Plants. The work of construction of 70 MGD waste water treatment plant at Coronation Pillar has been started in the month of September, 2016 and is proposed to be completed in 30 Months.

35. Increasing population has also resulted in demand for housing in the city. Under the new resettlement policy, JJ dwellers will be resettled in built up houses constructed under JNNURM to improve the quality of life of Jhuggi Jhopri / Slum dwellers. Delhi Government has constructed 55424 multi storied dwelling units for slum dwellers under JNNYRN or rehabilitation of eligible JJ

dwellers including Scheduled Caste families. Since inception of the modified policy for relocation of squatters, provisional allotment letters have been issued to 4323 families including 1768 SC families.

36. The new Building bye-laws have been adopted and notified for three Municipal Corporations, making them compliant with the stipulations under the Building Code 2005 for Seismic Zone – V.

37. To keep the city clean, the three Municipal Corporations clear about 10,000 MT (metric ton) of solid waste daily. The New Delhi Municipal Council has been declared Open Defecation Free on 12th August, 2016. For curbing the habit of mass defecation in open, DUSIB is providing Pay & Use Jan Suvidha Complexes having Community Toilets and Baths in JJ bastis. Swachh Delhi Mobile App has been re-launched on 16.11.2016 to upload complaints of garbage/malba and air pollution for removal thereof.

38. My Government has taken steps to improve the living conditions of people in the unauthorized colonies. The development work in unauthorized colonies is being expedited. For the current financial year, an outlay of Rs.1456 cr. was earmarked for undertaking the development in unauthorized colonies. Delhi Jal Board has provided water connections in 1175 unauthorized colonies till date.

39. Demand of Power in the city has been on the rise. The all time peak power demand of 6261 MW on 1/7/2016 was successfully met. To save electricity, all consumers are being provided four LED bulbs at Rs. 93/- each. Around 65 lakh LED Bulbs have been distributed to consumers.

40. To improve the Power distribution to the consumers 400KV sub-stations at Tughlaqabad, Dwarka and Maharani Bagh along with transmission lines are being installed by Power Grid Corporation of India Ltd. Land has been handed over at all three sites.

41. The Delhi Solar Policy 2016 has been notified. 32 MW solar installations have also been commissioned till date. The target till 2025 is 2000 MW, including solar installations on all government buildings. A tender for 84 MW has been floated. A generation based incentive of Rs.2/- per unit has been provided for domestic consumers.

42. The existing network of Delhi Metro is 189 Km. The work for Phase III is likely to be completed by June 2017. Consequent upon completion of this phase the network will be about 330 Km. Recently my Government has decided to construct eight corridors totalling 116 Km approximately under Phase IV of the expansion of Metro Rail Network. The work of the Phase IV is likely to be completed by the end of 2021.

43. To ensure safety and security of women passengers, Home Guards and Marshals are deployed in the DTC buses in the evening shift. DTC is providing ladies special trips during morning and evening peak hours.

44. My Government is actively engaged in monitoring, protecting and spreading of awareness about environmental concerns among the people of Delhi. Government has responded to control the environmental pollution and has taken a slew of measures to control air pollution in Delhi. Delhi Pollution Control Committee is monitoring ambient air quality in Delhi through six monitoring

stations. DPCC has imposed fines on construction projects which flouted the dust control norms. A graded Emergency Response Plan to deal with pollution is also being put in place.

45. On this occasion, I wish to reiterate that my Government is committed to provide citizen centric governance. I am confident that you all will extend your full cooperation and support to the endeavours of my Government for all round development of Delhi.

46. Hon'ble Speaker and Members of the august House, I have presented before you, in brief the highlights of some of the activities undertaken by my Government. The Dy. Chief Minister/ Finance Minister will spell out further details in his Budget Speech.

47. I extend my warm greetings and good wishes to all of you and wish you all success in your deliberations.

Jai Hind.

वित्तीय समितियों का चुनाव

अध्यक्ष महोदय : माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल जी वित्तीय समितियों के लिए निर्वाचन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

मुख्यमंत्री : (श्री अरविंद केजरीवाल) अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम-192 के उप-नियम (2), नियम 194 के उप-नियम (2) और नियम 196 के उप-नियम (2) के अनुसरण में इस सदन के सदस्य 01 अप्रैल, 2017 से आरंभ होने वाली कार्य अवधि के लिए लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से नौ-नौ सदस्यों का निर्वाचन करने के लिए अग्रसर होते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव सदन के सामने है:

जो इसके पक्ष में हैं वे हां कहें;
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,
प्रस्ताव पास हुआ।

प्रतिवेदन पर सहमति

अब श्री सोमनाथ भारती जी प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन दिनांक 18 जनवरी, 2017 को प्रस्तुत विशेषाधिकार समिति के चौथे प्रतिवेदन से सहमत है।

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं अपना प्रस्ताव सदन पटल पर रखूं, जो ये पूरी कार्यवाही हुई थी, मैं उसके बारे में सदन को अवगत कराना चाहता हूं।

21 जनवरी, 2016 को माननीय विजेन्द्र गुप्ता जी ने एक आर्टीकल लिखा था जो पब्लिश हुआ था पंजाब केसरी के अंदर। संविधान के ऊपर कुठाराघात

हुआ था। उनका मत उसके अनुसार यह था कि राज्य सभा को समाप्त कर दिया जाए। उन्होंने अपने आर्टीकल के अंदर बकायदा ये कहा कि वो सारे इंस्टीट्यूशन्स जो कि XXX[1] के काम के आड़े आ रहे हों उनको खत्म कर दिया जाए। उनका एक पैराग्राफ उसके अंदर जो था ''देश का दुर्भाग्य है कि अनेक छोटी पार्टियों द्वारा चुने गये राज्यसभा के सदस्य बहुमत के कारण पारित नहीं होने दे रहे हैं जिसके कारण देश का विकास प्रभावित हो रहा है।'' उन्होंने आगे उसके अंदर लिखा कि जब भी संसद चलती है, कार्यवाही में जानबूझकर गतिरोध पैदा किया जाता है, राज्य सभा को तो बदला लेने का हथियार बना दिया गया है। इसलिए अभी आवश्यक है कि राज्यसभा को समाप्त करके सिर्फ लोक सभा को रहने दिया जाए, ऐसा उन्होंने कहा। इससे आहत होकर के श्री के.सी. त्यागी साहब ने 28 जनवरी को एक नोटिस माननीय अध्यक्ष, राज्य सभा के यहां भेजा। वो नोटिस आपके जरिए हमारी समिति के पास पहुंचा और उसकी कार्यवाही शुरू हो गई। इसके बीच में उन्होंने 21 अप्रैल, 2016 को अपना उत्तर हमें दिया और दो बार मौका मांगा और हमने उनको मौका भी दिया। उसके बाद ये चले गये माननीय अध्यक्ष, राज्य सभा के पास और उन्हें कहा कि जी, हमसे गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। अनकंडीशनल माफी मांगी तो उसके संदर्भ में माननीय अध्यक्ष महोदय हमने सारी चीजें आपके जरिए समिति को बताएं कि जी, इन्होंने माफी मांग ली है, बेशक माफी मांगी है इसलिए ये आपको हम सूचना देते हैं। लेकिन चूंकि आपने आलरेडी फारवर्ड कर दिया है तो समिति के पास। समिति ने बकायदा मीटिंग्स ली और उस सैशन के दौरान विजेन्द्र गुप्ता जी आये और उन्होंने कहा कि भई, हम तो कुछ बात कहते हैं लेकिन जब उनसे कहा गया कि भई, आप तो माफी मांग लीजिए तो उसके सदर्भ में उन्होंने कहा कि चलो जी, हमने वहां माफी मांग

XXX[1] चिह्नित अंश अधयक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से हटाया गया।

ली है, हम उसी भावना से आपके सामने आए हैं, हमें माफ कर दिया जाए। तो उसको देखकर के क्योंकि विजेन्द्र गुप्ता जी छोटे–मोटे पद पर नहीं हैं, बहुत बड़े पद पर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, सदन बहुत गरिमा के साथ यहां उनकी बातों को सुनता भी है। इतनी बड़ी बात कि राज्य सभा को समाप्त कर दिया जाए, ये ऑलमोस्ट संविधान के ऊपर कुठाराघात है।

जब बात कर रहे हैं एण्टी नेशन की देश के अंदर छोटी–छोटी बातों को सबको एण्टी नेशनल बन जाता है और संविधान के अंदर ये बात कहकर के कि राज्य सभा को समाप्त कर दिया जाए, इतनी बड़ी बात इन्होंने कही। उसके बावजूद भी क्योंकि उन्होंने बगैर शर्त के माफी मांग ली और कहा कि ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। समिति ने उनकी बात को स्वीकार करते हुए क्योंकि वो हमारे पास ज्यादा ओपीनियन नहीं था, माननीय चेयरमैन, राज्यसभा ने उनको माफ कर दिया था, इसलिए हमें भी माफ करना पड़ा।

अध्यक्ष महोदय, उसके संदर्भ में मैं आज आपकी अनुमति से प्रस्तुत करता हूं। यह सदन दिनांक 18 जनवरी, 2017 को प्रस्तुत विशेषाधिकार समिति के चौथे प्रतिवेदन से सहमत है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव, इस पर क्या, विषय खत्म हो चुका है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, अभी चेयरमैन साहब ने जो यहां पर एक्सप्लेन किया है, उसके मुताबिक XXX के काम के आड़े आ रहे हैं ये शब्द जो हैं सदन की कार्यवाही से हटाये जाएं क्योंकि ये रिपोर्ट में न ही कोई विषय है, न आर्टीकल में कोई ये विषय है और मुझे लगता है कि न्याय नहीं होगा इस पूरे मामले में।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इसमें आपने कहा है।

XXX चिहि्नत अंश अधयक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से हटाया गया।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : इन्होनें कहा है कि XXX ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं इसमें...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : XXX काम के आड़े आती है इसलिए राज्य सभा को भंग किया जाए ऐसा कहा गया है। ये हमने explain करते वक्त सुना।

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी ये सब स्वीकर कर लीजिए।

श्री सोमनाथ भारती : हमने कहा राष्ट्रवाद को तो बदला लेने का हथियार बना दिया गया है, यहां तक कह दिया है इनके नेताओं ने।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : देखिये अध्यक्ष जी, ये जो आर्टीकल है।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, एक सेकेण्ड। मैं निर्णय दे रहा हूं ना जी। सोमनाथ जी बैठिये प्लीज।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ भारती : कैसा abolish?

श्री विजेन्द्र गुप्ता : देखिये, दूसरा हमारा ये कहना है कि जो बात वो पढ़ रहे हैं जो उन्होंने कहा था।

अध्यक्ष महोदय : नहीं अब विषय देखो विजेन्द्र जी, ये विषय मेरे सामने आ चुका है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शब्द थोड़ा इधर-उधर हो सकते हैं लेकिन जो भावनाएं माननीय उप-राष्ट्रपति जी ने मेरे पास भेजी, सेम वही कमोबेश वही भावनाएं यहां रखी गई और अब उस पर चर्चा होने में उचित नहीं रहेगा।

XXX[1] चिह्नित अंश अधयक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से हटाया गया।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ये शब्द हटा दीजिये XXX।

अध्यक्ष महोदय : XXX का नाम, सोमनाथ जी, मैं स्वीकार कर रहा हूं। हटा दीजिये, कोई दिक्कत नहीं।

अब प्रस्ताव सदन के सामने है:

जो इसके पक्ष में हैं वे हां कहें;
जो इसके विरोध में हैं वे न कहें;
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता
प्रस्ताव पास हुआ

प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण हेतु समयावधि बढ़ाने का प्रस्ताव

अब श्री राजेन्द्र पाल गौतम जी प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन बुराड़ी में स्थित राशन की दुकान के रद्द लाईसेन्स को पुनः जारी करने में कथित अनियमितता की जांच करने के लिए विशेष जांच समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की समयावधि को बढ़ाने से सहमत हैं। समिति अपनी रिपोर्ट मानीय अध्यक्ष महोदय को छठी विधानसभा को छठा सत्र प्रारंभ होने से पहले सौंपेगी। यह प्रस्ताव आपका, एक बार पढ़ दीजिये इसको।

श्री राजेन्द्र पाल गौतम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन बुराड़ी में स्थित राशन के रद्द लाईसेन्स को पुनः जारी करने में कथित अनियमितता की जांच करने की विधि से जांच समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की समयावधि को बढ़ाने से सहमत है परन्तु समिति अपनी रिपोर्ट माननीय अध्यक्ष महोदय को छठी विधानसभा का छठा सत्र प्रारंभ होने से पहले सौंपेगी।

XXX[1] चिह्नित अंश अधयक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से हटाया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव सदन के सामने है:

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ।

अब श्री कपिल मिश्रा जी माननीय पर्यटन मंत्री उप-राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर निम्नलिखित धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। यह सदन दिनांक 6 मार्च, 2017 को उप-राज्यपाल महोदय द्वारा विधानसभा को दिये गये अभिभाषण के लिए उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है, कपिल मिश्रा जी।

उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

पर्यटन एवं जल मंत्री (श्री कपिल मिश्रा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी सहमति से यह प्रस्ताव रखता हूं कि यह सदन दिनांक 6 मार्च, 2017 को उप-राज्यपाल महोदय द्वारा विधानसभा को दिये गये अभिभाषण के लिए उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है।

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ भारती जी, माननीय सदस्य धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। बोलेंगे? हां, बोलिये-बोलिये। मैंने तो समय दिया था, वो रूक गये बीच में।

पर्यटन एवं जल मंत्री : अच्छा, वो मेरी गलती हो गई।

अध्यक्ष महोदय, अभी उप-राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण सदन के

सामने प्रस्तुत किया और सरकार के द्वारा पिछले वर्ष में किये गये कार्यों का पूरा विवरण रखा। इन सभी विवरणों को जब हम सुन रहे थे, एक तो वो कार्यक्रमों का विवरण एक चीज होती है लेकिन स्वयं जब उप-राज्यपाल श्री अनिल बैजल साहब यहां पर आकर बोल रहे थे तो दिल से मेरे तो एक बात जरूर निकल रही थी:

'तुम आ गये हो, नूर आ गया है,
नहीं तो चिरागों से लौ जा रही थी'

आगे भविष्य के बारे में तो किसी ने नहीं देखा लेकिन जिस प्रकार से हमारा मौहल्ला क्लीनिक का काम हो या मिनिमम वेज की बात हो, पिछले कुछ समय में दिल्ली की जनता जिस निर्णयो का बेसब्री के साथ इंतजार कर रही थी, वो निर्णय हमने पूरे होते हुए देखे हैं और मुझे लगता है कि पूरा का पूरा शहर एक राहत की सांस ले रहा है कि जिस नीयत के साथ और ईमानदारी के साथ अरविंद केजरीवाल जी की सरकार अपने कामों को कर रही थी, अब वो जनता तक पहुंचने भी शुरू हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये कामों की जब चर्चा हुई तो शुरूआत हुई बुनियादी सुविधाओं से। बुनियादी सुविधाओं की बात हुई कि स्कूलों में कमरे बनाये जा रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधायें दी जा रही हैं, मौहल्ला क्लीनिक बनाये जा रहे हैं, पानी की लाईनें डाली जा रही हैं, मिनिमम वेजिज बढ़ाया जा रहा है। जब मैं इन बुनियादी सुविधाओं के बारे में, सरकार के कामों के बारे में सुन रहा था तो मुझे लगा कि देश में एक तरह से जैसे बुनियादी सुविधायें भी, जैसे दो तरह से देखने वाले मॉडल हैं एक मॉडल तो अरविंद केजरीवाल जी का है, जिसमें बुनियादी सुविधाओं का मतलब है स्कूल में कमरे बनें, बुनियादी सुविधाओं का मतलब है पीने का पानी घर तक पहुंचे, बुनियादी सुविधाओं का मतलब है कि स्वास्थ्य

सुविधायें पहुंचे और एक मॉडल जिसको बहुत जोर शोर से हल्ला मचा के देश में थोपने की कोशिश की जा रही है उसमें बुनियादी सुविधायें माने श्मशान घाट। श्मशान घाट बने या कब्रिस्तान बने, बने या न बने और कैसे बने। मुझे लगता है कि ये दो मॉडल बिल्कुल सामने के सामने हैं, आज देश के नजर आ रहे हैं कि ये बुनियादी सुविधाओं के नाम पर भी क्या बोल के चले जाते हैं और दूसरे जब करते हैं तो सच में लोग श्मशान घाट न ही पहुंचे, सरकार को उसके लिये काम करना चाहिये। शिक्षा के क्षेत्र में जो काम सरकार ने रखे, वो रखे हुए बड़े साधारण लगते हैं। ऐसा लगता है कि आठ हजार कमरे बनाये आठ हजार कमरों का मतलब क्या होता है, ये भी सोचना है।

एक नया सरकारी स्कूल बनता है अध्यक्ष महोदय, तो चालीस कमरों का नया सरकारी स्कूल बनता है। मैं जब सरकारी स्कूल में पढ़ा हमारा स्कूल टैंट में चलता था और आज मन करता है कि जब मनीष सिसौदिया जी के नेतृत्व में सरकारी स्कूलों में काम होते हुए देखते हैं, आज मन करता है दोबारा सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिये, तब जरूर मन में कसक होती थी कि काश! हम किसी और स्कूल में पढ़ते लेकिन आज जब अपने आसपास के अभिभावकों को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, आज ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज दोबारा भी एडमिशन लेना होता तो दिल्ली के सरकारी स्कूल में जाते। दौ सौ नये स्कूलों के बराबर का इन्फ्रास्ट्रक्चर दो साल में तैयार कर देना और पूरे देश में टोटल 200 नये सरकारी स्कूल नहीं बने होगें इस दौरान में जितने अकेले देश की राजधानी के अंदर इन्फ्रास्ट्रक्चर बना के दिया गया। मुझे लगता है कि अगर हम उसके परिप्रेक्ष्य में देखें कि देश के बाकी हिस्सों में क्या हुआ। अपने गवर्नेंस मॉडल के नाम पर सरकार में आये हुए लोगों के यहां क्या हुआ और यहां पर केवल बुनियादी सुविधाओं की बात चलने के नाम

पर क्या किया गया है उसको अगर तुलना करके देखें, तो तब इस काम की गंभीरता समझ में आती है। एक सरकारी स्कूल का प्रिंसीपल कैंब्रिज चला जाये, हावर्ड चला जाये, वहां से सीखकर आये और उसका बदलाव कैसा होता है, ये मैंने अपने सोनिया विहार में स्कूल में देखा है। सोनिया विहार की प्रथम पाली में एक प्रिंसीपल बदली गई और केवल प्रिसीपल के बदलते ही पूरा स्कूल का माहौल बदल गया, बच्चे बदल गये और मैं जब एनुअल-डे पर वहां उस स्कूल में गया तो उस स्कूल को देखकर दोबारा मुझे सोचना पड़ा कि क्या ये वही स्कूल है जिसमें मैं एक साल पहले आया था! जमीन आसमान का अंतर दिखाई दे रहा था! ये परिवर्तन है जिसमें बच्चों का आत्मविश्वास बढ रहा है, जिसमें बच्चे-बच्चियां ये सोच रहे हैं कि हम इस देश के एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं, देश के लिये अपना कर्तव्य भी निभा सकते हैं और अपने घर परिवार की जिम्मेदारी भी उठा सकते हैं। वो बुनियादी परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में इस सरकार ने करके दिखाया है। मुझे लगता है कि शायद वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता, वो किसी एक अभिभाषण में बयान नहीं सकता लेकिन उस मां बाप से जिसका बच्चा या बच्ची सरकारी स्कूल में जाता है, उसकी आंखों को देखने से पता लग जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में इस शहर के अंदर क्या करके दिखाया गया है। इस तरह के बदलाव करके दिखाये गये हैं, जब हम जॉब ओरिएंटेशन की बात करते हैं, कौशल केन्द्रों को बनाने की बात करते हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग की बात करते हैं। पेरेटंस-टीचर मीटिंग... सरकारी स्कूल में बारह साल पढ़ के निकल गये, मेरे माता पिता को किसी टीचर ने कभी मिलने के लिये नहीं बुलाया। आज पेरेटंस-टीचर मीटिंग सरकारी स्कूलों में हो रही है। टीचर, जो शायद बच्चों को, ये मानने को तैयार नहीं होते थे कि ये बच्चा भी इंसान है, एक हमारे जैसे परिवार का सदस्य है, उनको लगता था कि शायद ये बच्चा मजबूरी में स्कूल आ रहा है और मजबूरी में स्कूल

से घर जा रहा है। जब उसके माता पिता और टीचर आमने सामने खड़े होते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं, जब वो समझते हैं कि इन माता पिता के भी अपने बच्चों को लेकर वही सपने हैं जो उस टीचर के अपने बच्चे को लेकर देखे सपने हैं और जब वो संबंध आपस में बनता है तो मुझे लगता है कि मानवीयता शिक्षा के क्षेत्र में लाने का काम करता है, वो मनीष सिसौदिया जी ने किया है जो शायद अभिभाषण के शब्दों में विधानसभा की सरकारी भाषा के शब्दों में कभी भी नहीं बयान किया जा सकता।

मौहल्ला क्लीनिक की जब हम बात करते हैं कि 106 मौहल्ला क्लीनिक बन गये तो एक हजार मौहल्ला क्लीनिक बन के तैयार होने वाली हैं छह महीने के अंदर इस शहर में। तब ये भी समझना जरूरी है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि मौहल्ला क्लीनिक तो दिल्ली की किसी बस्ती में बन रही है और वहां अमेरिका में बैठे लोग कह रहे हैं कि यूएसए में भी यही माडल लागू होना है। तब ये समझ में आता है कि ये किस प्रकार का मूलभूत परिवर्तन सरकार चलाने के तरीके पर, काम करने के तरीके पर, राजनीति करने के तरीके में हो जाता है।

पांच करोड़ में एक डिस्पेंसरी बनती थी वो पांच करोड़ में बनने वाली पीली रंग की इमारत जिसमें न डाक्टर, न कंपाउंडर, न दवा न ईलाज ना पट्टी न टांका और आज बीस लाख में एअंरकणीशंड मौहल्ला क्लीनिक में दवाई भी, डाक्टर भी है, ईलाज भी और टैस्ट भी सारे फ्री हो रहे हैं। इसको समझने के लिये उस इंसान के पास जाना जरूरी है जो बड़े-बड़े अस्पतालों में छोटी-छोटी बीमारियों के लिये लाईन में लगा करता था और जिसका, सच में, महीनों महीनों बाद भी ईलाज का नंबर नहीं आता था तो किसी नीम हकीम के पास जाकर इलाज कराता था। बच गये तो बच गये, नहीं बचे तो नहीं

बचे। आज उसको बेस्ट ऑफ द मैडिकल फेसिलटीज उसके पड़ौस में मिल रही है, बाकी जगह देने की तैयारी है। वहां पर समझ में आता है कि आपका इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं हो रहा तो आप प्राइवेट में जा के इलाज करा लो अपना और खर्चा सरकार देगी। मुझे लगता है कि राम राज की बातें बहुत लोगों ने की हैं लेकिन राम राज दिल्ली में ही आ रही है।

पानी की इन्फ्रास्ट्रक्चर की जब हमने बात की। पानी की इन्फ्रास्ट्रक्चर में कितनी लाईन डाली, कितने किलोमीटर का नेटवर्क बिछाया, कितने टैंकर चलाये; ये सब बातें तो आ सकती हैं आंकडों में और कागज में। आंकडों में भी शायद पूरे देश में इतने स्केल पर कभी वाटर इन्फ्रास्ट्रक्चर कहीं डेवलप नहीं हुआ तो दिल्ली में हो रहा है इस वक्त। लेकिन आंकड़ों से अलग इसका जीवन पर क्या प्रभाव पडता है, द्वारका की तरफ से भी कुछ लोग मुझ से मिलने आये जो स्वास्थ्य एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने कहा कि वूमेन हेल्थ के ईश्यू पर आपकी सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है तो मुझे एकदम से समझ नहीं आया कि स्पेसीफिकली ये वूमेन हेल्थ के बारे में क्यों बोल रहे हैं तो उन्होंने कहा वूमेन हेल्थ के ऊपर सबसे बड़ा काम आपने ये किया कि आपने घर के अंदर पानी की लाईन दे दी तो मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा जब एक महिला टैकर की लाईन में लगती है, बाल्टी उठाती है, बाल्टी ले के जाती है, सीढ़ियां चढती है, अपने घर के अंदर ले के जाती है वो जो मानसिक तनाव और शारीरिक तनाव उसकी रीढ की हड्डी और शरीर के कई अंगों पर जो उसका प्रभाव पड़ता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला जाता है और केवल घर के अंदर नल खोल के पानी आपके घर में आ रहा है, इतने मात्र से पूरे के पूरे परिवार के मानसिक और शारिरिक स्वास्थ्य पर जमीन-आसमान का अंतर पड़ना शुरू हो जाता है। उस प्रकार की बात शायद कभी अभिभाषण में नहीं

आ सकती लेकिन ये लोगों की जिंदगियां बदली जा रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में हम स्कूल में कमरे बनाने की बात करते हैं। हम शिक्षा के क्षेत्र में टीचर्स की ट्रेनिंग की बात करते हैं। पेरेंटस-टीचर मीटिंग की बात करते हैं। कौशल केन्द्र की बात करते हैं लेकिन जो दूसरा गर्वनेंस माडल है, वो शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम करता है? जो हमने रामजस में देखा... अभी अपने ही देश में, अपने ही देश के नागरिकों को गद्दार का सर्टिफिकेट देने वाले शायद पहली बार सरकार में आकर बैठे हैं जिनको अपने ही देश के अगर आपको एक शहीद की बेटी की देशभक्ति का भरोसा नहीं है तो मुझे लगता है आप जरा सुबह जल्दी उठते हैं, लेट उठना शुरू करें। जल्दी उठकर जहां जाते हैं, वहां आपको देशभक्ति सिखाई नहीं जा रही। समझने की बात है लेकिन जिनको ये भी लगता है कि जब प्रेरणा ही गधों से ही ली जा रही हो तो फिर सरकार भी ऐसे ही चलेगी। अपने प्रेरणा स्रोत बदलें, अपने रोल मॉडल बदलें। किससे क्या सीखना है, वो बदलें। वो भी जरूरी है। तो जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के मॉडल के बारे में चर्चा हो, इसके काम के बारे में चर्चा हो किस प्रकार से... और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी सोमनाथ भारती जी ने बोला कि गुप्ता जी ने उसका विरोध किया कि प्रधानमंत्री जी के मिशन के रास्ते में जो आये उसको हटा देना चाहिये। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा लेकिन कह देना अभी नगर निगम का जब चुनाव हुआ तो यही कहना कि प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत अभियान के रास्ते में जो लोग खड़े हैं, उन्हें हटा दो। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं। इसी बात पर जायेंगे गली गली में दिल्ली की कि ये स्वच्छ भारत तो छोड़ो, स्वच्छ दिल्ली ही नहीं कर पाये, ऐसे लोगों को तो हटा ही देना चाहिए। गुप्ता जी, आपकी बात ले के जाएंगे अब की बारे पूरे शहर में....

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : वाकआउट कर लें?

जल एवं पर्यटन मंत्री : लेकिन अभी वाकआउट का टाईम नहीं हुआ है...(व्यवधान) तो कुल मिलाकर अभूतपूर्व कार्य न केवल डेवलेपमेंट के आंकड़ों के आधार पर, बल्कि दिल से जुड़कर, परिवारों से जुड़कर, जनता से जुड़कर इस शहर में पिछले दो सालों में देखा गया है उसकी चर्चा गली गली में है, घर घर में है। दुनिया भर के लोग इसकी बात करते हैं और जब काफी अन्नान जैसा शख्स किसी सरकार के काम की तारीफ करे तब आपको ये समझना होगा कि अब राजनीति से ऊपर उठ चुका है विकास का पानी। तो एक बार पुनः बहुत-बहुत आभार उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिये और ये प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत है।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। अब श्री सोमनाथ भारती जी, माननीय सदस्य धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि मैं अपना समर्थन का प्रस्ताव पर बोलूं, मैं दो बातें रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आज जो कुछ भी माननीय एलजी महोदय ने अपने अभिभाषण के दौरान पढ़ा और अभी कपिल भाई ने उसके ऊपर अपनी बातें रखी, उसको आगे बढ़ाते हुए कुछ कहना चाहता हूं। जब हमारा 2015 का चुनाव लड़ा जा रहा था, उस वक्त भाजपा के एक बहुत बड़े नेता ने कहा था कि किसकी सरकार चुननी है आपको, सरकार चुननी है आपको रामजादे की कि हरामजादे की। अब दिल्ली वालों ने सरकार चुनी है वो तो रामजादे की सरकार साबित हो रही है। उन्होंने सोचा था कि रामजादे की सरकार कोई

और लेकर आएगा लेकिन रामजादे की सरकार साबित हम हो पा रहे है। ये बहुत बड़े गर्व की बात है, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी दिल्ली के अंदर हो रहा है, केजरीवाल साहब के नेतृत्व के अंदर, ये कुछ अद्‌भुत हो रहा है, ये कुछ गजब हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और पानी के क्षेत्र में जो ये विकास कार्य का जो मॉडल हमारी सरकार ने दिया है, ये दुनिया भर के डिफरेंट मॉडल्स की स्टडी के बाद... मुझे लगता है कि ऐसा मॉडल हमारी सरकार ने दिया है, ये दुनिया भर के डिफरेंट मॉडल्स की स्टडी के बाद... मुझे लगता है कि ऐसा मॉडल कहीं नहीं मिलेगा। उसका कारण है, ये सरकार जिस मेन्डेट के साथ आई है वो मेन्डेट है आम आदमी को मजबूत करना। शिक्षा कें अंदर जो क्रांति हो रही है, ये कोई आम क्रांति नहीं है। हमारे नागरिकों को, बच्चों को शिक्षित करके जो उनके मजबूती दे रही है, ऐसा साहसिक कदम पूरे हिंदुस्तान के अंदर राजनैतिक इतिहास में कभी नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात एक कहानी के जरिए रखना चाहूंगा। एक राजा था उसका नाम स्टालिन। वो अपने देश में रशिया के अंदर पोलित ब्यूरो को एड्रेस कर रहे हैं कि किस तरह से राज चलाना चाहिए। एड्रोस करने के दौरान एक मुर्गा लेकर आए अपने साथ उस मुर्गे की एक पंख उघाड़ी, दूसरी पंख उघाड़ी, फिर तीसरा पंख उघाड़ा, पंख उघाड़ते मुर्गे का खून निकलने लगा, रूके नहीं उखाड़ते रहे जब तक मुर्गा नग्न नहीं हो गया। नग्न मुर्गा, खून निकलता हुआ मुर्गा उन्होंने फिर जमीन पर फेंक दिया और उसके बाद अपनी पॉकेट से कुछ दाने निकाले और वो नग्न मुर्गे के पास ले गए। वो दाने और वो नग्न मुर्गा! खून निकलता हुआ मुर्गा, दाना खाना लगा। तो फिर

कहते हैं ''पोलित ब्यूरो को ऐसे ही काम करना जनता के साथ। उसको मारो, कूटो, उसको सुविधाएं न दो, उसको तकलीफ दो, उसको शिक्षा न दो, स्वास्थ्य न दो, कुछ मत दो लेकिन आखिरी में 4 दानें लेकर चले जाओ जनता खुश हो जाती है।'' एक मॉडल है ये और एक मॉडल है ये जहां शिक्षा देकर के हमारी सरकार ने वो साहसिक कार्य किया है जो कि आम आदमी के अंदर से और बाहर से मजबूत करता है और ये मजबूती आने वाली सरकारों के लिए बहुत ही, और कोई और पार्टी चाहें कि ये मजबूती के साथ वो झेल लेंगे इस जनता को, असंभव है। इस मजबूत जनता को झेलने के लिए हमारे पास ताकत है। केजरीवाल साहब के नेतृत्व के अंदर जो सरकार बनी है, उन्होंने ये साहसिक कदम जो किया है, ये पूरे गवर्नेन्स मॉडल के अंदर आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ, कोई सरकार नहीं चाहती कि आम आदमी इतना मजबूत हो जाए, आम आदमी इतना शिक्षित हो जाए, आम आदमी इतना स्वस्थ हो जाए, आम इतना स्वस्थ हो जाए कि उसे सवाल पूछने का अधिकार, उसे नेताओं के सामने अपनी बात रखने का अधिकार मिल जाए। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ा सवाल है जो एजुकेशन के अंदर, स्किल एजुकेशन के अंदर, हैल्थ केयर के अंदर, पेंशन का एमाउंट बढ़ाया, अपना मिनिमम वेजिज बढ़ाया, नाईट शैल्टर्स बढ़ाया, इन सारे कामों को कुल मिलाकर अगर देखें तो इस सरकार के इस साहसिक कदम ने आने वाली सरकारें और जो देश में और सरकारें हैं, सबको आज विचलित कर दिया है कि इतना काम अगर इस सरकार ने कर दिया तो यही मॉडल पूरे देश में चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, 11 मार्च के बाद आ जाएगा पंजाब में ये मॉडल, ये मॉडल भी लगेगा और भी जो सरकार की प्लानिंग है, वो भी लगेगी। पूरे हिन्दुस्तान के अंदर चर्चा है ये कि ऐसी सरकार जिसने शिक्षा के अंदर आम आदमी को मजबूत करने का, स्वास्थ्य के अंदर आम आदमी को मजबूत करने का जो प्रेरणादायक काम किया है, इसका पैरेलल कहां से मिलेगा इतिहास

में! अध्यक्ष महोदय, हमारे इस मॉडल के कारण, हमारे इस मॉडल के बाद जो स्टालिन वाला मुर्गा है, वो हमारी जनता मुर्गा नहीं बन पाएंगी अध्यक्ष महोदय। हमारी जनता मुर्गा नहीं बन सकती। इस शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर और इतनी साहसिक कदम को लेकर के जो जनता के अंदर सम्मान पैदा हुआ है, आज कपिल भाई ने कहा कि फिर स्कूल जाने का मौका मिला तो जाना चाहते है।

अभी आज सबेरे-सबेरे मैं मॉर्निंग में घुम रहा था पार्क के अंदर तो बात हुई कि इतने सारे काम कर दोगे तो और किसी के पास क्या बचेगा करने को। लोग अब इस तरह की बातें करने लगे हैं। क्योंकि दो साल के अंदर आपने शिक्षा में भी क्रान्ति ला दी, स्वास्थ्य में भी क्रांति ला दी। अब तो दवाइयां मुफ्त मिल रही हैं, सारे टैस्ट मुफ्त होंगे, 30 दिन के अंदर अगर सरकारी अस्पताल के अंदर किसी का ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो ऑपरेशन वो प्राइवेट से करा सकता है। इतने सारे काम अगर हो गए और जो हो रहे हैं, उसके बाद किसको मौका मिलेगा यहां पर गर्वनेंस मिलने का।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने सरकार की माननीय एलजी महोदय ने जो आज अभिभाषण पढ़ा है, उनके अभिभाषण के अंदर एक-एक शब्द जो सरकार ने साकार करने का प्रयास किया दिल्ली के अंदर, सरकार को बधाई देता हूं, अपने साथियों को बधाई देता हूं, अपनी पार्टी को बधाई देता हूं कि जिस उद्देश्य के साथ, जिस मंशा के साथ सरकार आई थी, उससे कई गुणा ज्यादा काम कर पा रही है। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद के साथ चूंकि प्रस्ताव कपिल भाई लेकर आए थे तो उनके सपोर्ट में एक प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि सदन दिनांक 6 मार्च, 2017 को उपराज्यपाल महोदय द्वारा विधान सभा को दिए गए अभिभाषण के लिए उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद।

सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण जो प्रस्ताव कपिल मिश्रा जी, माननीय मंत्री जी ने सदन में रखा है जिसका समर्थन माननीय सदस्य सोमनाथ भारती जी ने किया है, इस प्रस्ताव पर कल हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं सदन की कार्यवाही स्थगित करूं एक बहुत अच्छी सूचना जो मन को प्रफुल्लित करेगी, दे रहा हूं, ''यह अत्यधिक हर्ष का विषय है कि हमारे माननीय सदस्य श्री विशेष रवि जी का गत दिनों सामूहिक विवाह कार्यक्रम, सबसे बड़ी बात जिस पर मैं जोर दे रहा हूं सामूहिक विवाह कार्यक्रम में विवाह हुआ है। मैं विशेष रवि जी को हार्दिक बधाई देता हूं तथा उनके वैवाहिक जीवन के लिए शुभ कामनाएं देता हूं। उन्होंने सामूहिक विवाह के तहत पुनीत कार्य करके जन प्रतिनिधियों के लिए अनुक्रणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है, बहुत-बहुत बधाई।''. .. वो पार्टी दे रहे है आज। प्रवीण देखमुख जी की और से मेरा इशारा है मुझे ये अवसर जल्दी प्रदान करें।

अब सदन की कार्यवाही 7 मार्च, 2017 को अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। मै सभी माननीय सदस्यों और पत्रकार बंधुओं से अनुरोध करता हूं कि वो भोजन के लिए सीएम कमेटी रूम के पीछे लॉन में पधारें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(सदन की कार्यवाही 7 मार्च, 2017 को अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

विषय सूची

सत्र-5 भाग (1) सोमवार, 6 मार्च, 2017/15 फाल्गुन, 1938 (शक) अंक-44

क्रसं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1-2
2.	उपराज्यपाल महोदय का अभिभाषण	4-27
3.	वित्तीय समितियों का चुनाव	28
4.	प्रतिवेदन पर सहमति	28-32
5.	प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण हेतु समयावधि बढ़ाने का प्रस्ताव	32-33
6.	उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा	33-43
7.	सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात	44